







## पावर एंजेल्स सशक्तिकरण व सुगमकर्ता का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर्म इकट्ठी के अन्तर्गत पावर एंजेल्स सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता प्रदान तथा तीन पैक्चर एंजेल के साथ कैसे बालिकाओं के सेल्प स्टीम को

कि विद्यालय स्तर पर कैसे मीना मंच को बालिकाओं के लिए सशक्त और उपयोगी बनाया जा सकता है तथा तीन पैक्चर एंजेल के साथ कैसे बालिकाओं के सेल्प स्टीम को

टाइप, गुड टच बैड टच, चाइल्ड हेल्पलाइन, एनोमिया के कारण व बचाव, सेल्पिंग भोजन, बॉडी शेपिंग व बालिकाओं के शारीरिक परिवर्तन पर असर को सुगम कर्ता बालिकाओं की बेहतर ढंग से काउंसिलिंग कर उनकी समस्याओं का निदान करते रहें। प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर ख्वाशिक्षा अधिकारी जसरा अखेल वर्षा वर्षा ने कहा, सभी सुगमकर्ता शिक्षिकाओं अपने प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी का विद्यालय में उपयोग कर बालिकाओं के विकास उनकी नियमित उपस्थिति और उनकी समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाना अंत में सभी प्रशिक्षणार्थी शिक्षिकाओं और सन्दर्भदाता को प्रशिक्षण सहभागी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। प्रशिक्षण में नाजिया सुल्ताना, निशा त्रिपाठी, ऊर्ध्वा यादव, सुमन भट्टेनिया, बुशरा खानम, सध्या सिंह, ज्योति जायसवाल, स्वाती गौतम, ममता गुप्ता, कंचन सिंह, रीना देवी आदि शिक्षिकाओं उपस्थित रहीं।

ओवन आमंत्रित करना वाले अध्यर्थी सरकारी कर्मचारी हो या रहा हो,



दिवसीय प्रशिक्षण बीआरसी धूरपुर जसरा में शनिवार को संपन्न हो गया। इस कार्यशाला में उच्च प्राथमिक विद्यालय की 44 महिला शिक्षिकाओं ने सन्दर्भदाता द्वाय श्रावण शर्मा व अतुल कुमार जायसवाल ने बताया

द्वार गेट डॉ भीमराव अंबेडकर स्मृति द्वारा, के नाम से ही बने गेट

(आधुनिक समाचार नेटवर्क) सोनभद्र। आजाद समाज पार्टी

उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, भी संविधान निर्माता बाबा साहब

सोनभद्र को अवगत कराया की

सोनभद्र जिला मुख्यालय रोड

स्थित द्वार गेट डॉ भीमराव

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर के चित्र पर पृष्ठ अपित

करते हैं सर द्वाकाते हैं लैकिन

भाजपा के लोग जब बाबा साहब

जल्द नहीं बात तो किया जाएगा

धरना प्रदर्शन। रविकान्त जिलाध्यक्ष

आजाद समाज पार्टी ने बताया कि

अंबेडकर के चित्र के बाद भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया

गया ऐसा लगता है की नाम को

मिटाना चाहती है सरकार, डॉ

अंबेडकर स्मृति द्वार के नाम से गेट

कराने के लिए कार्य शुरू किया

गया। 6 मईने दिन जाने

के बाद भी कार्य शुरू भी किया



# सम्पादकीय

महादेव ने क्यों काटा ब्रह्मा का पांचवां सिर, संस्कृति के पन्नों से होता है खुलासा भगवान् शिव ने परमपिता ब्रह्मा द्वेषा। परंतु वह जहाँ भी गई

भगवान् शब्द वर ने परमपाता ब्रह्मा की ऐसी कामासक्त दशा देखी, तो उन्हें पिता के मन में पुत्री के लिए ऐसा भाव देखकर क्रोध आ गया। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के रचनाकर्म का प्रयास जब आगे नहीं बढ़ा, तो ब्रह्मा ने अपने ही शरीर को दो भागों में विभक्त कर लिया। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग स्त्री का हो गया। पुरुष का नाम 'मनु' और स्त्री का नाम 'ब्राह्मी' था। इस तरह मनु, ब्रह्मा का पुत्र और ब्राह्मी, उनकी पुत्री हुई। परतु देवर्षि नारद ने किसी कारणवश ब्रह्मा को यह शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा के मन में अपनी ही पुत्री ब्राह्मी के प्रति कामना उत्पन्न हो गई। ब्राह्मी का सौर्दृश्य अप्रितम था, जिसे देखकर सृष्टिकर्ता अपनी रचना पर मुग्ध हो गए। वह ब्राह्मी को टकटकी लगाए देखते रहे। उनकी आंखों में अपनी पुत्री के लिए सन्ने हौं और आशीष का भाव नहीं, अपितु उसे प्राप्त करने की कामना थी। ब्राह्मी ने जब परमपिता ब्रह्मा की आंखों में इस तरह का भाव देखा, तो वह घबराकर मुझी और ब्रह्मा के बाई ओर जाकर खड़ी हो गई। परतु ब्रह्मा ऐसे मोहित थे कि ब्राह्मी को देखने के लिए बाई ओर उनका एक सिर प्रकट हो गया। यह देखकर ब्राह्मी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह फिर मुझी और ब्रह्मा के दाहिनी ओर चली गई। हांगा। परतु वह जहा भी गई, ब्रह्मा उसका पीछा करते रहे। ब्रह्मा से बचने के लिए ब्राह्मी ने पशु-पक्षियों का रूप तक धारण करके देखा। परतु फिर भी सफलता नहीं मिली। ब्राह्मी घोड़ी बनी, तो ब्रह्मा घोड़ा बनकर आ गए, उसने गाय का रूप धारा, तो ब्रह्मा बैल बन गए। वह हिरण्णी में बदल गई, तो ब्रह्मा भी हिरण्ण बन गए। इस तरह ब्राह्मी ने पशु, सरीसुप, पक्षी, कीट, स्तनधारी आदि सभी श्रेणियों में रूप धारण किए, परतु हर बार उसने ब्रह्मा को नर रूप में अपने सामने पाया। ब्राह्मी ने इस तरह एक-एक करके सौ रूप बदले, जिसके चलते उसका नाम पड़ा- शतरूपा। अधिकतर ग्रन्थों में ब्रह्मा की संतान के रूप में मनु और शतरूपा का ही नाम मिलता है। भगवान् शिव ने परमपिता ब्रह्मा की ऐसी कामासक्त दशा देखी, तो उन्हें पिता के मन में पुत्री के लिए ऐसा भाव देखकर क्रोध आ गया। तब शिव ने ब्रह्मा का ऊपर निकला पांचवां सिर काट डाला, जिसके बाद ब्रह्मा के केवल चार सिर रह गए। शिव ने ब्रह्मा का सिर तो काट दिया, किंतु वह कटा सिर शिव के हाथ से चिपक गया। यह देखकर शिव चकित थे। फिर उन्हें अहसास हुआ कि ब्रह्मा का शोश काटकर उनसे ब्रह्म-हत्या का पाप हो गया, जिसके दंडस्वरूप ब्रह्मा का सिर उनके हाथ से चिपक गया।



मतदान किया, उससे दोनों 'लड़कों' के होश फाखा हैं। दोनों दलों के प्रवक्ता और समर्थक अब लोकतंत्र की दुहाई देकर विलाप कर रहे हैं। दरअसल, इन सब का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग

ठाक रहे थे कि बिहार में ऑपरेशन लालटेन होग और भाजपा तथा जदयू के विधायक दल को तोड़ा जाएगा। अलग बात है कि जब बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार ने विश्वास मत पेश किया तो राजद के ही विधायक पाला

नहीं कहा चला गया था। पराजनीतिक इतिहास के आईने में दल-बदल समाजवादी पार्टी ने 1990 के दशक और 2003 में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के विधायिकों से दल बदल कराया था, तब उनकी नैतिकता कहां खो गई थी? कांग्रेस

रोकने के संदर्भ में किसी तरह का प्रावधान ही नहीं किया था। भारत के सविधान पर वेस्टमिस्टर प्रणाली का प्रभाव है जिसमें विधायिका के सदस्यों से अपनी लोकतांत्रिक चेतना के आधार पर निन्यच्य की स्वतंत्रता परिकल्पित रही है। 1951 से लेकर

तत्कालीन सोवियत संघ में बसी हुई थी कोयले की वह कहानी, जिसने उसके इतिहास और भगोल आए मजदूरों को स्टैकनोवाइट्स कहा जा रहा है। यानी वे श्रमिक, जो अपनी मेहनत से खुश और सखी वेल्स के मिथाइल टैफिल शहर में है, जहां शुरुआती लोहा उद्योग विकसित हुआ था। यहां आपको मशीन अब आपको बोल्शेविक क्रांति के बीचों-बीच ले आई, जिसके असर से द्व्यज की कंपनी

दोनों को प्रभावित किया। वही कोयला जो कभी स्टालिन की ताकत था, सौवियत रूस के विघटन की वजह बन गया। रूस यूक्रेन युद्ध की तीसरी बरसी पर हम देख सकते हैं कि कभी ऊर्जा के पावर हाउस रहे रूस से दुनिया का कारोबार बंद है। यूरोप न कभी नहीं सोचा था कि दुनिया के सबसे बड़े कोयला क्षेत्रों, यानी रूस के कुजनेत्स और यूक्रेन के डोनेस्क का पड़ोसी होने के बावजूद उन्हें अटलांटिक पार अमेरिका से कोयला मंगाना पड़ेगा। रूस को भी अनुमान नहीं था कि कोयले की, जो उसके औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा निर्माता है, खदानों में याताया जा सकता। दशम शताब्दी

है। स्टालिन कह रहे हैं, 'लाइफ हैं ज बिकम हैपियर कामरेड्स, लाइफ हैं ज बिकम हैपियर...' यही वह संदेश था, जिस पर संगीत व गीत बनाए गए। हालांकि बाद के दशकों में स्टालिन का यह संदेश व्यांग्य बन गया। कम्युनिस्टों के स्टार मजदूर स्टैकनोव रूस और यूक्रेन के सीमावर्ती इलाके डोनबास से आते हैं, जिसे डोनेट्स रीजन कहा जाता है। इसका एक हिस्सा रूस में और दूसरा यूक्रेन के पास

जॉन व्यूज के किस्से सुनने को मिलेंगे। वह एक लोहा मिल में इंजीनियर के बैठे थे। किस्मत और नसीहतों की चक्रवर्ती दीढ़ियां चढ़ते हुए व्यूज पहुंच गए मिलवाल आयरन एंड शिपबिल्डिंग वर्क्स, जो तब सबसे बड़ी लोहा कंपनी थी। व्यूज को इस कंपनी का निदेशक बनाया गया और वह निकल पड़े कोयले की तलाश में। टाइम मशीन में आपको दिखाइ देगा कि 1869 में व्यूज करीब आठ जहाजों पर

के विदेशी कर्मचारियों और मालिकों को देश छोड़ना पड़ा, लेकिन उद्योग फलता-फूलता रहा। युजकोवा शहर का नाम बदल कर सिटी स्टालिनो कर दिया गया। टाइम मैगजीन के कवर पर विराजने वाले मजदूर स्टैकनोव ने इस इलाके को दुनिया में मशहूर कर दिया। टाइम मशीन में स्टैकनोव का किस्सा सुनते हुए हम आ गए हैं 1985 म। ठीक पहचाना आपने, ये मिखाइल गोर्बाचेव हैं, जो हैं रूस के पेरोस्त्रोइका यानी नए आर्थिक सुधार के प्रवर्तक। गोर्बाचेव ने

**बनाते हैं महत्वपूर्ण उपकरण नहीं  
उपहनने वाला होता है**

कदमों का सच्चा तक का जाफ़ा का आप करेंगे क्या? महत्वपूर्ण उपकरण नहीं, बल्कि उन्हें पहनने वाला होता है। पिछले कुछ वर्षों में अपने शरीर का स्वस्थ रखना डाटा साइंस में डिग्री लेने जैसा लगाने लगा है। शरीर में गुकोज, पसीने, नीद,



शहरा इलाका हा 2014 म रुस से संघर्ष की शुरूआत से पहले यहां का समृद्ध कोयला और खनन उद्योग युक्तेन की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत था। इस सफर के लिए टाइम मशीन में बैठने से पहले आप भी खारकीव, डोनेस्क जैसे शहरों के नाम सुन चुके होंगे। मारियोपोल का बंदरगाह शहर, जिस पर रुस ने मौत बरसाई है, भी इसी समृद्ध कोयला और औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है। टाइम मशीन अब तेजी से उड़ान भर कर 18वीं सदी के ब्रिटेन में आ गई है। यह ब्रिटेन में औद्योगिक

इस वरान इलाक म उद्योग नाम की चीज नहीं थी। ह्यूजू ने यहां एक मेटलर्जिकल और रेल पटरी बनाने की फैक्टरी लगाई। काला सागर करीब ही था, जिससे तैयार माल ब्रिटेन पहुंचने लगा। यह बोल्टेविक युग से पहले की बात है, जब आपको दिखेगा कि जॉन ह्यूजू रस्स के औदयोगिकीकरण के प्रवर्तक बन गए हैं। डोनबास के इलाके में मजदूर जुटने लगे हैं। कोयला और लोहा उद्योग चमक रहा है। जॉन ह्यूजू ने यहां एक शहर बसाया, जिसे युजकोवा नाम दिया गया था। इस शहर में मजदूरों को ब्रिटेन

से उड़त हुए आपका दिखाए कि डानवों से साइबैरिया तक करीब तीन लाख मजदूरों ने रूस की एक-तिहाई कोयला खदानें बन्द कर दी हैं। अब गोर्बाचेव को सुधार वापस लेने पड़े। येलसिन ने सोवियत रूस के गणतंत्र के साथ नए समझौते का दबाव बनाया। इस बीच सोवियत रूस बिखर गया। कम्युनिस्टों के गढ़ पूर्वी यूरोप का नक्शा ही बदल गया। वही कोयला, जो कभी स्टालिन की ताकत था, सोवियत रूस के विघ्टन की वजह बन गया। टाइम मशीन अब रूस-यूक्रेन युद्ध की तीसरी बरसी पर मास्को में उतर रही है। ऊर्जा स्रोतों

# इतिहास के आईने में दल-बदल का समीकरण

भारत में दल बदल का इतिहास नया नहीं है। जो आजकल उठते-बैठते लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उन्हें स्मृति भ्रंश का रोग न होने पाए, इसलिए कुछ तथ्य पेश करने आवश्यक है। संविधान निर्माताओं ने तो दल-बदल रोकने के संदर्भ में किसी तरह का प्रावधान ही नहीं किया था। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस अंदाज में अपनी पार्टी के हिप को धूता बताकर अंतरात्मा की आवाज पर भारतीय और धनबल के प्रयोग के बूते कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी एलायंस के घटक दलों के विधायक दलों में फूट डालने का काम किया है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर बनाने की योजना के तहत है। कांग्रेस और उसके बगलबच्चा दल जब भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के विधायकों पर डारे डालते हैं, तब उसे वह बेहद लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं। इधर, अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की सहयोगी बदलकर नीतीश के समर्थन में खड़े हो गए, जो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में अपने प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघी के पराभव पर चूढ़ियां तोड़ रही हैं, वही कांग्रेस कर्नाटक में भाजपा विधायकों से क्रॉस वॉटिंग कर लेने पर इतराने से बाज नहीं आती। इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी पाला बदलने वाले विधायकों को नीतिकता का पाठ पढ़ा रही है, जबकि उसने भी ओम प्रकाश राजभर के एक विधायक से जब अपने पक्ष में क्रॉस वॉटिंग ने विगत विधानसभा में ही राजस्थान में बसणा के सभी विधायकों को तोड़ लिया था, तब लोकतंत्र की दुहाई उसने बिसार दी थी। दरअसल लोकतंत्र की परिभाषा को तमाम कांग्रेसी बगलबच्चों ने अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित करने का शाशल शुरू से ही पाल रखा है। भारत में दल बदल का इतिहास नया नहीं है। जो आजकल उठते-बैठते लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उन्हें स्मृति भ्रंश का रोग न होने पाए, इसलिए कुछ तथ्य पेश करने आवश्यक है।

ने विगत् विधानसभा में ही राजस्थान में बसपा के सभी विधायकों को तोड़ लिया था, तब लोकतंत्र की दुर्वाई उसने बिसार दी थी। दरअसल लोकतंत्र की परिभाषा को तमाम कांग्रेसी बगलबच्चों ने अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तित करने का शाशाल शुरू से ही पाल रखा है। भारत में दल बदल का इतिहास नया नहीं है। जो आजकल उठते-बैठते लोकतंत्र की दुर्वाई देते हैं, उन्हें स्पृति भ्रंश का रोग न होने पाए, इसलिए कुछ तथ्य पेश करने आवश्यक है।

1967 तक विविध दलों से कुल 542 विधायकों ने अपने दल से पाला बदलकर कांग्रेस में प्रवेश किया, तब तक सब कुछ चंगा था और इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक चौला भी पहनाया गया था। 1967 में संविद (संयुक्त विधायक दल) सरकार की सफलता के बाद बड़े पैमाने पर कांग्रेस छोड़कर विधायक विरोधी दलों में शामिल होने लगे, तब कांग्रेस सरकार ने यशवंत राव चहाण के नेतृत्व में दल बदल के बारे में एक समिति का गठन किया। इस समिति का गठन

दी। चौधरी चरण सिंह को कुछ काल के लिए प्रधानमंत्री पद से हफले नवाजा और फिर उनकी सरकारांत से समर्थन वापस खींचकर उन्हें अपदस्थ कर दिया। अब किसी भी विधानसभा या लोकसभा में विधायक दल या संसदीय दल में विभाजन के लिए एक तिहाई सदस्यों का साथ आना आवश्यक था। इसके बाद भी राजीव गांधी ने स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार और चंद्रशेखर की सरकार को गिराने का खेल खेला। तमिलनाडु की विधानसभा में विधायकों

1967 तक विविध दलों से कुल 542 विधायकों ने अपने दल से पाला बदलकर कांग्रेस में प्रवेश किया, तब तक सब कुछ चंगा था और इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक चोला भी पहनाया गया था। 1967 में संविद (संयुक्त विधायक दल) सरकार की सफलता के बाद बड़े पैमाने पर कांग्रेस छोड़कर विधायक विरोधी दलों में शामिल होने लगे, तब कांग्रेस सरकार ने यशवंत राव चहाण के नेतृत्व में दल बदल के बारे में एक समिति का गठन किया। इस समिति का गठन लोकसभा में दल-बदल के संदर्भ में पारित एक प्रस्ताव के चलते हुआ। फरवरी 1967 से मार्च 1968 के बीच 12 महीने की समयावधि में कुल 438 विधायकों ने दल बदल कर लिया। तब कांग्रेस की आंखें चौधियाई। यशवंत राव चहाण समिति की रिपोर्ट में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भूपेश गुप्ता ने जो नोट लिखा है, वह कांग्रेस की अवसरवादी राजनीति को अच्छे से बेनकाब करता है। 1967 तक जो दल-बदल हो रहे थे, इसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा था। किन्तु चौथे आम चुनाव के बाद विविध राज्यों में कांग्रेस की पराजय के बाद दल-बदल कर कांग्रेसी विधायक विपक्षियों के साथ सरकार बनाने लगे। 1967 के बाद जिन विधायकों ने पाला बदला था, उनमें सात राज्यों के 210 विधायक शामिल थे, जिनमें से 116 मंत्री बन गए थे। संकेत साफ था कि सरकार बनाने के लिए मंत्री पद का लोभ विधायकों को पाला बदलने के लिए प्रेरित कर रहा था। 1970 के दशक में पहले कांग्रेस ने और बाद में जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार दल-बदल प्रतिबंधक कानून बनाने पर विचार करना प्रारंभ किया। हालांकि, 1979 में कांग्रेस ने जनता पार्टी में फूट डालकर मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी। चौधरी चरण सिंह को कुछ काल के लिए प्रधानमंत्री पद से पहले नवाजा और फिर उनकी सरकार से समर्थन वापस खींचकर उहाँसे अपदस्थ कर दिया। अब किसी भी विधानसभा या लोकसभा में विधायक दल या संसदीय दल में विभाजन के लिए एक तिहाई सदस्यों का साथ आना आवश्यक था। इसके बाद भी राजीव गांधी ने स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार और चंद्रशेखर की सरकार को गिराने का खेल खेला। तमिलनाडु की विधानसभा में एक तिहाई विधायक दल के नियम की धज्जी स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ने 1987 में उड़ाई। जो शरद पवार इन दिनों दो-तिहाई विधायक दल के अंजीत पवार के साथ जाने के बावजूद महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारेंकर के फैसले को अलोकतांत्रिक करार दे रहे हैं, वही 1991 में एक तिहाई की तुलना में कम विधायक होने के बावजूद शिवसेना से अलग हुए छान भुजबल के नेतृत्व वाले 12 विधायकों को तत्कालीन महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष मधुकर राव चौधरी के फैसले को संविधान के अनुकूल बता रहे थे। तमाम विधानसभाओं के ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें विविध विधानसभाओं के विविध अध्यक्षों ने एक तिहाई और दो तिहाई के मानक की धज्जियां उड़ाई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग विधायक दल के लिए दो तिहाई का मानक तय किया। बावजूद इसके ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिसमें विधायक दल की तोड़फोड़ को संविधान सम्मत ठहराया गया। अब कांग्रेस और उसके बगलबच्चा दल आए दिन गच्छा खा रहे हैं, इसलिए उनके लोकतंत्र और संविधान की परिभाषा आजकल बदली-बदली नजर आ रही है।

आयोग की चाहत और सरकार की कोशिश  
यह कहकर कि देश में गरीब आबादी के बल पांच फीसदी रह गई है, नीति आयोग को गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सरकार गरीबी भले दूर करने में सफल न हो पा रही हो, लेकिन गरीबों को अपनी नजरों से ओझल करने की पुरजोर कोशिश जरुर कर रही है। अगर आप किसी सुबह उठें और अखबार में एक हैंडलाइन पढ़ें कि 'कोई गरीब नहीं, भारत ने किया गरीबी का उन्मूलन', तो हैरत नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग दरअसल यही चाहता है कि आप इस पर भरोसा करें। योजना आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था को सरकार का प्रवक्ता बना कर रख दिया गया है। पहले उसने धोषणा की कि देश में बहुआयामी गरीबी 11.28 फीसदी है और अब इसके सीईओ ने यह खोज की है कि भारत में गरीब आबादी पांच फीसद से ज्यादा नहीं है। सीईओ ने यह आश्चर्यजनक दावा राष्ट्रीय नमूना आयोग गंभीरता से तर्क देता है कि कोई भी व्यक्ति, जिसका मासिक खर्च (भोजन और गैर-खाद्य) ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2,112 रुपये या 70 रुपये प्रतिदिन है, वह गरीब नहीं है? या शहरी क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति, जिसका मासिक खर्च 3,157 रुपये या प्रतिदिन 100 रुपये है, गरीब नहीं है? मेरा सुझाव है कि सरकार नीति आयोग के प्रत्येक अधिकारी को 2,100 रुपये देकर एक महीने गंवांगे में जाकर रहने के लिए भेजे और फिर यह बताने के लिए कहे कि उसका जीवन कितना समृद्ध था। जो वास्तविकताएं सामने आईएसीईएस ने खुलासा किया कि उपभोग में भोजन की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में घटकर 46 और शहरी क्षेत्रों में 39 फीसदी हो गई है। यह शायद सच है, क्योंकि आय व व्यय तो बढ़ रहा है, लेकिन खाद्य उपभोग का मल्य वही बना हुआ है या बेहद धीमी गति से बढ़ रहा है। बाकी आंकड़े भी



सामाजिक समूह बन हुए हैं। वे औसत से नीचे, तो ओबीसी औसत के करीब हैं। केवल 'अन्य' हैं, जो औसत के ऊपर हैं। राज्यवार आंकड़ों को देखें, तो सबसे गरीब नागरिक वे हैं, जो छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में रहते हैं, जिनका एमपीसीई ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय औसत से नीचे है। अगर हम शहरी क्षेत्रों के लिए एमपीसीई के राष्ट्रीय औसत पर विचार करें, तो राज्यों के नामों में थोड़ा ही फर्क पाएंगे। इन राज्यों में लंबे समय तक भाजपा और गैर-कांग्रेसी सरकारों का शासन रहा है। फिजल प्रचार पर न जाएं, तो हैरत की बात है कि 1995 से भाजपा द्वारा शासित गुजरात एमपीसीई के मामले में ग्रामीण और



